प्रेम कुमार हांडा

बनाम

राष्ट्रीय आवास बैंक और एक अन्य

महेश ग्रोवर न्यायमूर्ति के समक्ष ,

प्रेम कुमार हांडा - याचिकाकर्ता

बनाम

राष्ट्रीय आवास बैंक और एक अन्य - उत्तरदाता

2008 का सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 7533

2 दिसम्बर, 2009

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - राष्ट्रीय आवास बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2003 - क्षेत्रीय अधिकार - राष्ट्रीय आवास बैंक से सेवानिवृत्ति - पेंशन के लिए दावा - न तो प्रधान कार्यालय और न ही उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित कोई शाखा / अधीनस्थ कार्यालय - याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति के बाद बसता है और उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ संचार प्राप्त करता है - क्या उच्च न्यायालय किसी याचिका पर विचार करने के लिए सक्षम है ? नहीं, याचिका खारिज

अभिनिधारित किया गया कि इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए आह्वान को उचित ठहराने के लिए किए गए कथन किसी भी तरह से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि, इस न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की शक्ति थी ताकि ऐसे आदेश पारित किए जा सकें जो प्राधिकरण को प्रभावित कर सकते हैं जो इसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादियों का नई दिल्ली को छोड़कर देश में कहीं भी कोई अधीनस्थ कार्यालय या शाखा नहीं है और केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति के बाद पंचकूला में बस गया है और उसे वहां कुछ संचार प्राप्त हुआ है, येह तथ्य इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के दायरे का विस्तार नहीं करेगा। इसलिए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार करता है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके पास कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है।

याचिकाकर्ता को , यदि ऐसा सलाह दी जाए , तो वह सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। (Paras 16 & 17)

याचिकाकर्ता की ओर से अतुल गौड़ एडवोकेट सहित वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एस. मित्तल

प्रतिवादी की ओर से वकील, आलोक जग्गा।

निर्णय

महेश ग्रोवर, न्यायमूर्ति :

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत वर्तमान याचिका इस अनुरोध के साथ दायर की गई है कि परमादेश की प्रकृति में एक निदेश जारी किया जाए जिसमें प्रतिवादियों को राष्ट्रीय आवास बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2003 (संक्षेप में, विनियमों) के अंतर्गत याचिकाकर्ता को देय पेंशन का भुगतान आज तक ब्याज सहित करने का निदेश दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 20 अप्रैल 2006 (अनुलग्नक पी 17) के आदेश को रद्द करने के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करने का एक और अनुरोध किया गया है।

(2) याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि वह 31 अक्टूबर, 2000 को कार्यकारी निदेशक के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक (इसके बाद 'प्रतिवादी नंबर 1' के रूप में वर्णित) की सेवा से सेवानिवृत्त हुए। इससे पहले, उन्होंने शुरुआती वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक में शामिल होने के बाद अपने करियर को शानदार बनाया था और उसके बाद 1 मार्च, 1989 से प्रतिवादी नंबर 1 में शामिल हो गए और विभिन्न पदोन्नति अर्जित करने के बाद, कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि विनियमों को वर्ष 2003 में अधिसूचित किया गया था और इसके अनुसार, वह विनियमों के विनियम 2 (क्यू) और 34 (2) के साथ पढ़े गए विनियमन 2 (डी) में उल्लिखित दस महीनों की औसत परिलब्धियों के आधार पर पेंशन प्राप्त करने का हकदार था और इस तथ्य के बावजूद कि वह नियमित रूप से उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जा रहा था और उनके प्रयासों के अनुसरण में, उन्हें प्रतिवादी संख्या

प्रेम कुमार हांडा

बनाम

राष्ट्रीय आवास बैंक और एक अन्य

2 से दिनांक 20 अप्रैल, 2006 को पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि मामला विचाराधीन है और उसी पत्र में, निम्नलिखित दो विकल्प दिए गए थे - .

"(l) लागू डीआर (भाग-II) के साथ जीएम (यानी दिसंबर 1997) के रूप में अपनी सेवा तक पेंशन के लिए अर्हक सेवा पर विचार करना। इसके परिणामस्वरूप अनुबंध-I में दर्शाए अनुसार बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

(2). लागू डीआर (भाग-III) के साथ ईडी के रूप में आपकी सेवा (अक्टूबर, 2000 में आपकी सेवानिवृत्ति तक) सहित पेंशन के लिए अर्हक सेवा पर विचार करना। इसके परिणामस्वरूप 1 मई, 2005 से 31 जनवरी, 2006 तक महंगाई राहत में कमी के कारण भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली होगी जैसा कि अनुपत्र 11 में दर्शाया गया है।

(3). याचिकाकर्ता ने अपने दावे को संतुष्ट करने के लिए ये अच्छे विकल्प नहीं पाए और इसलिए, उन्होंने इसे खारिज कर दिया और अपने दावे पर कायम रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर, उन्हें तत्काल रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

(4). नोटिस जारी होने पर, उत्तरदाताओं ने उपस्थिति दर्ज की और अपना लिखित बयान दायर किया जिसमें उन्होंने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि इस न्यायालय के पास इस रिट याचिका पर विचार करने का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 का प्रमुख कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी कोई शाखा या उसका कोई अधीनस्थ इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित नहीं है।

(5). जब मामले को सुनवाई के लिए लिया गया, तो प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने याचिका का जवाब देने के लिए इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार पर सवाल उठाने के लिए प्रारंभिक प्रस्तुतियों में निहित आपत्ति को बलपूर्वक उठाया।

(6). चूंकि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि अधिकार क्षेत्र का मामला मामले की पूरी जड़ तक जाता है, इसलिए पक्षकारों के विद्वान वकील को इस मुद्दे पर तर्कों को संबोधित करने का निर्देश देना उचित समझा गया और यही कारण है कि इस मामले के तथ्यों को संक्षेप में देखा गया है।

(7) याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि सेवानिवृत्ति के बाद याचिकाकर्ता पंचकूला में रह रहा है और उसके तथा प्रतिवादियों के बीच पूरा पत्राचार पंचकूला में हुआ है जहां उसे अनुलग्नक-17 पत्र भी दिया गया है। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि इस न्यायालय के पास निश्चित रूप से तत्काल याचिका पर विचार करने का अधिकार है और विशेष रूप से जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (2) में इस तरह की आकस्मिकता का प्रावधान है। उन्होंने **तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम उत्पल कुमार बसु और अन्य**[1] पर भरोसा किया, जिसमें इसे निम्नानुसार माना गया है -

"अनुच्छेद 226 के तहत एक उच्च न्यायालय संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति का उपयोग कर सकता है यदि कार्यवाही का कारण पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उन क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न हुआ था जिनके संबंध में वह अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है। इसके बावजूद कि सरकार या प्राधिकरण की सीट, या उस व्यक्ति का निवास जिसके खिलाफ निर्देश, आदेश या रिट जारी किया गया है, उक्त क्षेत्रों के भीतर नहीं है। "कार्यवाही का कारण" शब्द का अर्थ है तथ्यों का वह पुलिंदा, जिसे याचिकाकर्ता को साबित करना होगा, यदि उसे अदालत द्वारा उसके पक्ष में निर्णय देने का हकदार बनाया जाए। इसलिए, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी की आपत्ति का निर्धारण करते समय अदालत को कार्यवाही के कारण के समर्थन में दिए गए सभी तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, हालांकि उक्त तथ्यों की शुद्धता या अन्यथा के बारे में जांच शुरू किए बिना। इस प्रकार क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के सवाल का फैसला याचिका में दिए गए तथ्यों पर किया जाना चाहिए, याचिका में किए गए कथनों की सच्चाई या अन्यथा से कोई फर्क नहीं पड़ता "

(8) दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वकील ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का खंडन किया और तर्क दिया कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान पर रह रहा था और उसे अपने अधिकारों को प्रभावित करने वाला आदेश या पत्र प्राप्त हुआ था, किसी विशेष उच्च न्यायालय को अपने अधिकारों का फैसला

[1] (1994) 4 SCC 711

करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा।. अपनी दलील के समर्थन में, उन्होंने **गुरदयाल सिंह बनाम भारतीय खाद्य निगम**[2] में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर भरोसा किया।

(9) मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर सोच-समझकर विचार किया है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया

(10) इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधानों के अनुसार, उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है यदि कार्यवाही का कारण पूरी तरह से या आंशिक रूप से इसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न हुआ है। अनुच्छेद 226 के खंड (2) के अनुसार, खंड (1) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके भी किया जा सकता है, जिसके भीतर कार्यवाही का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उत्पन्न हो सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर नहीं है, ऐसी शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। लेकिन, सार यह है कि कार्यवाही का कारण कहां से उत्पन्न होता है।

(1l) **राजस्थान राज्य और अन्य बनाम स्वाइका प्रॉपर्टीज और अन्य**[3] मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल नोटिस की सेवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के अर्थ के भीतर अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए कार्यवाही का अभिन्न अंग नहीं है।

(12) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के मामले (सुप्रा) में, उनके लॉर्डशिप ने निम्नानुसार देखा:—

"वर्तमान मामले में भले ही रिट याचिका में कही गई बातों को सही माना जाए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्यवाही का एक हिस्सा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ था। विज्ञापन में ही उल्लेख किया गया था कि निविदाएं नई दिल्ली में ईआईएल को प्रस्तुत की जानी चाहिए; यह कि नई दिल्ली में उनकी जांच की जाएगी और निविदाकर्ता को ठेका देने या न देने का अंतिम निर्णय नई दिल्ली में लिया जाएगा। निस्संदेह, ठेके का कार्य गुजरात के . हजीरा में किया जाना था। इसलिए, केवल इसलिए कि एनआईसीसीओ ने कलकत्ता में विज्ञापन पढ़ा, कलकत्ता से प्रस्ताव प्रस्तुत किया, कलकत्ता से अभ्यावेदन दिया और कलकत्ता से फैक्स

---

[2] 2006 (3) SCT 97
[3] 1985 (3) SCT 217

संदेश भेजे और कलकत्ता में उसका उत्तर प्राप्त किया, कार्यवाही के कारण का एक अभिन्न अंग बनने वाले तथ्यों का गठन नहीं करेगा।

(13) इसी तरह इस न्यायालय का **गुरनाम सिंह बनाम भारत संघ**[4]मामले में दिया गया निर्णय भी इसी तरह का है, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि किसी आदेश या नोटिस की सेवा को न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए नहीं माना जा सकता है।

(14) **नकुल देव सिंह बनाम डिप्टी कमांडेंट**[5], मामले में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया: –

"तथ्य यह है कि एक व्यक्ति जिसे राज्य के बाहर सेवा में रहते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, उसे उस बर्खास्तगी का परिणाम भुगतना होगा, जब वह बेरोजगार होकर अपने मूल स्थान पर है, यह एक ऐसा तथ्य नहीं है जो तथ्यों के पुलिंदा का गठन करता है जो उसके विरुद्ध की गई उसकी बर्खास्तगी की कार्यवाही को चुनौती देता है।यह अधिकार उन्हें पहले तब मिला था जब उन्हें राज्य के बाहर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और उन्होंने अपना रोजगार खो दिया था। इसी तरह, जब उसके द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर की जाती है जो इस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और उस अपील को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय में विलय तब होता है, अपील जब खारिज कर दी जाती है न कि जब अपीलकर्ता को आदेश प्राप्त होता है। एक याचिका को अपनी कार्यवाही के एक हिस्से के रूप में दलील देने की आवश्यकता, इस तथ्य से है कि उसकी अपील पूरी तरह से या आंशिक रूप से खारिज कर दी गई थी, न कि यह तथ्य कि आदेश उसे सूचित किया गया था। यह दलील केवल यह दिखाने के लिए प्रासंगिक है कि कार्यवाही के कारण का अधिकार उनके पक्ष में कब आया। आदेश की प्राप्ति केवल उसे पहले से अर्जित कारण पर कार्यवाही का अधिकार देती है और उसे विपक्ष में उठाए गए अवरोधों या सीमाओं की दलील को पूरा करने में सक्षम बनाती है। यह कि किसी कार्यवाही के परिणाम बड़े अर्थों में किसी व्यक्ति को उसके स्थान पर भुगतने पड़ते हैं, यह मानने का आधार नहीं है कि जिस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में मूल स्थान स्थित है, वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट

[4] 1994 (3) SCT 386
[5] 2000 (1) SCT 217

याचिका पर विचार करने के लिए भी सक्षम है। जब किसी व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाता है या रैंक में कम कर दिया जाता है, तो उसे उन परिणामों का सामना उस जगह करना पड़ता है जहां वह प्रासंगिक समय पर कार्यरत था, न कि अपने मूल स्थान पर, जहां वह अपनी बर्खास्तगी पर सेवानिवृत्त हो सकता था।

(15) यदि कानून की उपरोक्त स्थिति को वर्तमान मामले के तथ्यों से जोड़ा जाता है, तो रिट याचिका में किए गए कथन स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि याचिकाकर्ता ने यह दिखाने का भी प्रयास नहीं किया कि नोटिस प्राप्त करने और उसके नोटिस का जवाब देने के अलावा इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उसे किस कारण से कार्यवाही का सामना करना पड़ा। याचिका पर दायर जवाब में प्रारंभिक आपत्तियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, उन्होंने एक प्रत्युत्तर दायर किया, जिसमें पहली बार, उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने को सही ठहराने की कोशिश की। इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के आह्वान को न्यायोचित ठहराने के लिए जो कथन दिए गए हैं, उनका अवलोकन किया जाना चाहिए और उनकी सराहना के लिए उन्हें उसके अंतर्गत पुन: प्रस्तुत किया जाता है –

याचिका में कहा गया है, 'याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि वह तीन अक्टूबर 2000 को राष्ट्रीय आवास बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ था। उस समय, प्रतिवादी संख्या 1 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने को नियंत्रित करने वाले कोई पेंशन नियम नहीं थे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधिनियम की धारा) के तहत अधिनियम के तहत पेंशन विनियम तैयार किए गए थे और 7 मई, 2003 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे। सेवानिवृत्ति के समय, याचिकाकर्ता को भविष्य निधि विनियमों द्वारा शासित किया गया था, जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा समान राशि का योगदान दिया गया था। जैसा कि याचिकाकर्ता ने किया था। पेंशन विनियमों के प्रकाशन पर, प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता के विकल्पों के बारे में पूछा, जो उस समय पंचकूला में एच. नंबर 262, सेक्टर 4, पंचकूला में बसे हुए थे। इस संबंध में मुझे उत्तरदाता संख्या 1 के एजेंट, अर्थात् भारत सरकार के डाक और तार विभाग द्वारा उन्हें दिया गया था। इस पत्र के माध्यम से, प्रतिवादी नंबर 1 ने याचिकाकर्ता के विकल्प से पूछा कि क्या वह भविष्य निधि द्वारा शासित रहना चाहता है या 2003 के पेंशन विनियमों द्वारा शासित होना चाहता है। यह 1 जुलाई,

2003 के कार्यालय आदेश संख्या 23/2003 के माध्यम से है। याचिकाकर्ता ने 11 जुलाई, 2003 के अपने पत्र के माध्यम से पेंशन विनियमों द्वारा शासित होने के विकल्प का प्रयोग किया, जो पहले से ही अनुलग्नक पी/2 के रूप में रिकॉर्ड पर है।

वर्तमान याचिका में विवाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सेवाओं को जारी रखने या बंद करने के संबंध में नहीं है, जिसके लिए यह निर्धारित करना आवश्यक हो सकता है कि प्रधान कार्यालय या प्रतिवादी संख्या 1 की कोई शाखा या कार्यालय है इस माननीय न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित हो । वर्तमान याचिका में विवाद का मामला 2003 के पेंशन विनियमों के अनुसार याचिकाकर्ता को स्वीकार्य पेंशन की राशि के सही निर्धारण से संबंधित है, जो बैंक की सेवा से याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के लगभग 3 साल बाद लागू हुआ था। कार्यवाही का कारण या कम से कम इसका एक हिस्सा पंचकूला में याचिकाकर्ता ने इसलिए उठाया गया है क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा याचिकाकर्ता को संबोधित विभिन्न संचार और उनके एजेंट भारतीय डाक सेवा के माध्यम से उसे वहीं भेजे गए हैं।

(16) मुझे डर है कि ; उपरोक्त कथन किसी भी तरह से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि इस न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की शक्ति थी ताकि ऐसे आदेश पारित किए जा सकें जो प्राधिकरण को प्रभावित कर सकते हैं जो इसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादियों का नई दिल्ली को छोड़कर देश में कहीं भी कोई अधीनस्थ कार्यालय या शाखा नहीं है और केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति के बाद पंचकूला में बस गया है और वहां कुछ संचार प्राप्त किया है, इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के दायरे का विस्तार नहीं करेगा।

(17) इसलिए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार करता है कि ऐसा करने के लिए उसके पास कोई क्षेत्रीय अधिकार

क्षेत्र नहीं है। याचिकाकर्ता, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, तो सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

(18) तदनुसार, यह याचिका खारिज की जाती है।

(19) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सभी लंबित सिविल विविध आवेदन को भी खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

ओमेश

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी